पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

इंद्रदेव यादव

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2024 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 1348

03 दिसम्बर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ.
अंशुमान)

विचार के लिए मुद्दा

क्या जगदीशपुर थाना कांड संख्या 219/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 503/2017 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश XIV, भागलपुर द्वारा दिया गया दोषमुक्ति आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 372, परंतुक—आरोपी/प्रतिवादी सं. 2 को बरी किए जाने के विरुद्ध अपील—एफआईआर में, सूचक ने प्रतिवादी सं. 2 का नाम नहीं लिया था और उसने एफआईआर में नामित सभी अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप लगाए थे—ट्रायल कोर्ट ने अपराध के लिए आठ आरोपियों को दोषी ठहराया और प्रतिवादी सं. 2 को बरी कर दिया—पी. डब्लू. 2 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी सं. 2 का नाम निपटाया कि उसने अन्य आरोपियों को गोली चलाने का आदेश दिया था; और इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी सं. 2 के साथ उसकी पूर्व दुश्मनी थी—पी. डब्लू. 6, जांच अधिकारी ने भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह गवाही दी कि स्वतंत्र गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी सं. 2 को पूर्व दुश्मनी के कारण अपीलकर्ता द्वारा झूठा फंसाया गया था ।

निर्णय: ट्रायल कोर्ट ने अन्य सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है—जब अभियोजन पक्ष प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा था, ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए उसे बरी करना उचित समझा—यदि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट

द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए और अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में आरोपी के पक्ष में दोहरी धारणा है—सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के तहत निर्दोषता की धारणा उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न हो जाए, दूसरी बात, आरोपी ने अपनी बरी सुनिश्चित कर ली है, उसकी निर्दोषता की धारणा ट्रायल कोर्ट द्वारा और अधिक पुष्ट, पुनः पुष्टि और मजबूत हुई है—ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ बरी करने का आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है बरी करने का आदेश—अपील खारिज। (पैराग्राफ 11, 12, 14, 17, 18)

न्याय दृष्टान्त

चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एससीसी 415—भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

बरी किये जाने के विरुद्ध अपील; स्वतंत्र गवाह; प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा; जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न कर दिया जाए।

प्रकरण से उत्पन्न

जगदीशपुर थाना कांड संख्या 219/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 503/2017 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश XIV, भागलपुर द्वारा दिनांक 07.10.2024 को दिए गए बरी आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री रंजन कुमार झा, अधिवक्ता; श्री मितुनजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री बिनोद बिहारी सिंह, एपीपी।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 1348

थाना-कांड संख्या-219 वर्ष-2014 थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर से उत्पन्न

=====

इंद्रदेव यादव पिता स्वर्गीय कुलेश्वर यादव निवासी ग्राम-कोला नारायणपुर,

थाना जगदीशपुर, जिला-भागलपुर

..... अपीलकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. भैरो यादव पिता स्वर्गीय सिधू यादव निवासी ग्राम-कोला नारायणपुर, थाना जगदीशपुर, जिला-भागलपुर।

..... प्रतिवादीओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से : श्री रंजन कुमार झा, अधिवक्ता

श्री मिर्तुजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी-राज्य की ओर से : श्री बिनोद बिहारी सिंह, एपीपी

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 03-12-2024

विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार झा को सुना गया, जिनकी सहायता अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मित्तुजय कुमार और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान एपीपी श्री बिनोद बिहारी सिंह ने की।

2. वर्तमान अपील अपीलकर्ता/मूल सूचक/पीड़ित की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 के तहत, भागलपुर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश XIV द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 503/2017 में दिनांक 07.10.2024 को दिए गए बरी आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो जगदीशपुर पीएस केस संख्या 219/2014 से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा वर्तमान प्रतिवादी संख्या 2/मूल आरोपी को बरी कर दिया गया है।

3. अभियोक्ता की *फर्दबयान* के आधार पर अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.08.2014 को लगभग 09.30 बजे प्रातः सूचक, उनके भाई सागर यादव, इन्द्रदेव यादव, बिलाश यादव, कैलाश यादव, बुधन यादव एवं संजय यादव अपने खेत में धान की फसल रोपने के लिए मौजूद थे। इसी बीच प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तगण बिन्नो यादव, इन्नो यादव, होरिल यादव, जजन यादव, बिल्लो यादव, पंकज यादव, हप्पो यादव, पलाटी यादव, माटू यादव एवं धनजी यादव घातक हथियार से लैस होकर वहां पहुंचे तथा उक्त खेत में धान रोपने से मना किया, जिस पर अभियोक्ता ने कहा कि वे रोपना बंद कर देंगे, लेकिन प्रशासन को बुलाएंगे तथा प्रशासन के अनुसार कार्यवाही करेंगे, जिसके बाद अभियुक्तगण उनके साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे तथा रोपने से भी रोका। आगे आरोप है कि बिन्नो यादव एवं इन्नो यादव ने मुखबिर के सिर पर मस्कट के बट से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। सज्जन यादव एवं पंकज यादव ने बुधन यादव

के सिर पर पिस्तौल के बट से प्रहार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। आगे आरोप है कि हिप्पो यादव ने बुधन यादव के पीठ पर धारदार खंती से प्रहार कर दिया। आगे आरोप है कि पंकज यादव ने बबलू यादव पर लाठी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। आगे आरोप है कि बिन्नो यादव एवं इन्नो यादव ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिस पर सूचक एवं अन्य लोग जमीन पर लेटकर छिप गए। आगे आरोप है कि आरोपियों ने उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस आने का शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। घटना का कारण भूमि विवाद है। सूचक के फर्दबयान के आधार पर जगदीशपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 17.08.2014 को सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 504 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मामला संख्या 219/2014 पंजीकृत किया गया।

4. जांच पूरी होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 504 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 31.01.2016 के आरोप पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 504 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत संज्ञान लिया गया।

5. 10.05 2018 को आरोपी व्यक्तियों अर्थात् इनो यादव, होरिल यादव, बिलाश यादव उर्फ बिल्लो, जजन यादव, भैरो यादव (यहाँ अपीलकर्ता), पतुली यादव, नाटू यादव, धौजी यादव और पंकज यादव के खिलाफ धारा 147,

148, 341, 323, 324 आईपीसी और धारा 307/149 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपियों को हिंदी में आरोप पढ़कर सुनाए गए और समझाए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. संबंधित मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 209 के तहत मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया क्योंकि यह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था।

7. सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की तथा बचाव पक्ष ने भी एक गवाह से पूछताछ की।

8. मुकदमे के समापन के बाद, ट्रायल कोर्ट ने निजी प्रतिवादी/आरोपी को बरी कर दिया और इसलिए, सूचक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

9. वर्तमान अपीलकर्ता/मूल सूचक/पीडित के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान की प्रति तथा अन्य सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने उसी का संदर्भ दिया तथा उसके बाद तर्क दिया कि दो घायल गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विशेष रूप से यह बयान दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में आदेश देने वाला है तथा जब प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संबंधित व्यक्तियों को मारने का आदेश दिया गया, तो अन्य अभियुक्तों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष के दो गवाह घायल हो गए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने आठ अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 147, 148 तथा 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान प्रतिवादी

संख्या 2 को दोषमुक्त कर दिया है, तथा इसलिए अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध पारित दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की है। यह तर्क दिया गया है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जिससे यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 भी कथित घटना में शामिल है। विद्वान अधिवक्त ने आगे कहा कि यहां तक कि दो घायल गवाहों ने भी अदालत के समक्ष विशेष रूप से गवाही दी है और प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसने आदेश दिया, जिसके बाद अन्य आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें वे घायल हो गए। इसलिए, विद्वान अधिवक्त ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादी संख्या 2 को दोषी ठहराया जाए।

10. दूसरी ओर, विद्वान एपीपी ने उचित रूप से प्रस्तुत किया है कि आज तक, राज्य ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। हालांकि, विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है।

11. हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई सामग्री का अध्ययन किया है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना 17.08.2014 को सुबह लगभग 9:30 बजे हुई थी और प्राथमिकी पीडब्लू-2 द्वारा दर्ज की गई थी। हालांकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्राथमिकी में, सूचक ने प्रतिवादी संख्या 2 का नाम नहीं लिया था और उसने उन सभी अन्य

आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाया था जिनका नाम उक्त प्राथमिकी में है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पीडब्लू-2 ने न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने "गोली मारो" का आदेश दिया तथा उसके बाद अन्य अभियुक्तों ने अपने पास मौजूद हथियारों से हमला किया। उसके बयान से यह भी पता चलता है कि पीडब्लू-2 ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 [भैरो यादव (मुखिया)] के साथ उसकी पूर्व दुश्मनी है।

12. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पीडब्लू-6, जांच अधिकारी, बीरेंद्र कुमार सिंह ने भी न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि उसने स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् अमित यादव, पप्पू यादव और अर्जुन यादव का बयान दर्ज किया था तथा उक्त व्यक्तियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि भैरो यादव को पूर्व दुश्मनी के कारण इंद्रदेव यादव द्वारा झूठा फंसाया गया है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि उपर्युक्त स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाहों की जांच करने में विफल रहा है।

13. यह आगे प्रकट करेगा कि मुखबिर और गवाहों ने पुलिस के समक्ष दिए गए अपने आगे के बयान में प्रतिवादी संख्या 2 को फंसाया है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके झूठे आरोप के बारे में दी गई दलील को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से यह देखा है कि प्रतिवादी संख्या 2 की घटनास्थल पर उपस्थिति और घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को मारने का आदेश देने के संबंध में संदेह उठाया गया है।

14. इस स्तर पर, यह देखना उचित है कि ट्रायल कोर्ट ने अन्य सभी आठ आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148 और 149 के साथ धारा

307 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। हालांकि, जब अभियोजन पक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, तो ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उसे बरी करना उचित समझा।

15. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और अन्य सामग्री को देखने के बाद, हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है।

16. इस स्तर पर, हम **चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देना चाहेंगे, जो **(2007) 4 एससीसी 415** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैराग्राफ 42 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:-

“42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे विचार से, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं: -

(1) अपीलीय अदालत के पास सबूतों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिस पर बरी करने का आदेश आधारित है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग और अपीलीय अदालत द्वारा तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, “पर्याप्त और सम्मोहक कारण”, “अच्छे और पर्याप्त आधार”, “बहुत मजबूत परिस्थितियाँ”, “विकृत निष्कर्ष”, “स्पष्ट गलतियाँ” आदि का उद्देश्य दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील

में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को सीमित करना नहीं है। इस तरह की वाक्यांश रचनाएँ "भाषा के अतिरेक" की प्रकृति की होती हैं, जो साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुँचने की न्यायालय की शक्ति को सीमित करने की अपेक्षा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने की अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर बल देती हैं।

(4) हालांकि, अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोष होने की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए। दूसरे, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी निर्दोषता की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और मजबूत, पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि दो उचित आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो अभियुक्त के पक्ष में दोहरा अनुमान लगाया जा सकता है। यदि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी से यह कहा जा सकता है कि यदि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए तथा अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरा अनुमान है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति

को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिए जाने के पश्चात, उसकी निर्दोषता की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और भी सुदृढ, पुष्ट और मजबूत किया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, की जांच की जाती है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध दोषमुक्ति का आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है, और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 के अंतर्गत सूचक द्वारा दायर वर्तमान दोषमुक्ति अपील में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(डॉ. अंशुमान, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।